कलेक्ट्रेट कर्मियों के तेवर तल्ख

देहरादून (एसएनबी)। नये स्टाफिंग पैटर्न को लेकर जिलाधिकारी और कलेक्ट्रेट कर्मियों में ठन गई है। कर्मचारी पुरानी व्यवस्था की मांग पर अड़े हुए हैं, तो जिलाधिकारी नई व्यवस्था को लागू करने की कोशिश में लगे हैं। जिसके चलते डीएम के नये स्टाफिंग पैटर्न को वापस लेने के बाद संघ को थमाए पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख न होने पर कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों ने फिर से कार्यबहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आम जनता को खासी परेशानी हो रही है जबकि उत्तरांचल मिनिस्टीरियल फेडरेशन ने भी कलेक्ट्रेट कर्मियों को समर्थन दिया है।

- जिलाधिकारी पर कर्मचारियों का भरोसा तोड़ने का आरोप, आरपार की लड़ाई का निर्णय
- मिनिस्टीरियल फेडरेशन महासंघ ने भी दिया कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन

धरना देते मिनिस्टीरियल कर्मचारी।

कर्मियों की हड़ताल के चलते खाली पड़ा कार्यालय।

बृहस्पतिवार को संयुक्त कार्यालय परिसर के बाहर कलेक्ट्रेट कर्मी कार्यबहिष्कार के बाद धरने पर बैठे। धरना स्थल पर कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करने के साथ ही कर्मचारियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा 30 जुलाई से कलेक्ट्रेट कर्मी नये स्टाफिंग पैटर्न को वापस लेने की मांग को लेकर कार्यबहिष्कार पर हैं। कर्मचारियों ने कहा कि चार जुलाई को जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को बातचीत के लिये बुलाया था, लेकिन उनके न जाने पर देर सांय नये स्टाफिंग पैटर्न को वापस लेने और पुरानी व्यवस्था के मुताबिक काम करने के लिये कह दिया गया। जिसके बाद मंगलवार को कर्मचारी पुरानी व्यवस्था के अनुरूप अपने-अपने पटल पर बैठ गए। लेकिन बुधवार को प्रशासन से मिले पत्र में कर्मचारियों को नये पैटर्न के मुताबिक ही काम करने को कहा गया। इसके साथ ही पत्र में शब्दों को तोड़मरोड़ कर लिखा गया। जिस पर गुस्साए कर्मचारियों ने तुरंत काम बंद कर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कार्यबहिष्कार का ऐलान कर धरने पर बैठ गए।

कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा डीएम द्वारा कर्मचारियों का भरोसा तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई आरपार की होगी। इसके साथ ही उन्होंने डीएम के स्थानांतरण की भी मांग की है। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पिछले दस दिन से आम जनता को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। जनता के रोजमर्रा के काम अधर में लटके हुए हैं। उत्तरांचल मिनिस्टीरियल फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री सुनील दत्त कोठारी ने कलेक्ट्रेट कर्मियों की हड़ताल को पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया है। धरने पर बैठने वालों में जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार, जिला सचिव देवेन्द्र सुन्द्रियाल, आशीष जोशी, राजेन्द्र रावत, अजय गोयल, अनिल कुमार, रविन्द्र कुमार, सुरेन्द्र सिंह आदि कर्मचारी बैठे थे।

आंदोलन को और उग्र करेंगे अमीन

देहरादून (एसएनबी)। उत्तराखण्ड राजस्व संग्रह अमीन संघ ने मांगों को लेकर सरकार की अनदेखी से खफा होकर आंदोलन को और उग्र कर दिया है। संघ के प्रांतीय नेतृत्व ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ राजस्व संग्रह कर्मी अपने-अपने क्षेत्र के मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों का घिराव करेंगे। इसके साथ ही उन पर संघ की मांगों का शासनादेश कराने के लिये दवाब बनाएंगे।

बृहस्पतिवार को राजस्व संग्रहकर्मी तयशुदा स्थल पर संघ के बैनर तले सातवें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। संग्रह अमीनों की हड़ताल के चलते सरकार को हर दिन करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन शासन में बैठे आला अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं है।

धरना स्थल पर सभा में वक्ताओं ने पूर्व में हुए आंदोलनों को याद करते हुए कहा कि संगठन ने पूर्व में भी कई ऐतिहासिक आंदोलन किये हैं और सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा अभी आंदोलन को एक सप्ताह हुआ है। जब तक मांगें नहीं मानी जाती है, तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। वक्ताओं ने शासन में बैठे सचिवों को सलाह दी है कि जब से राजस्व संग्रह अमीन संवर्ग बना है, तब से वेतन व पदोन्नति में इस संवर्ग के साथ भेदभाव किया गया है।

उन्होंने कहा प्रत्येक वेतन आयोग में संग्रह अमीन के वेतन को कम करते रहे हैं और स्थिति यह हो गई है कि राजस्व संवर्ग में निम्म स्तर का कर्मचारी कर दिया गया है। लेकिन अब संवर्ग अपने अधिकारों के लिये सजग हो गया है। उन्होंने कहा अब सम्मान जनक ग्रेड-पे, सम्मानजनक पदोन्नति और मूल नियुक्ति सेवा का लाभ से कम कुछ भी लेना संवर्ग को स्वीकार्य नहीं करेगा।

- प्रांतीय नेतृत्व ने अपने क्षेत्रों में मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों के घेराव का लिया निर्णय
- संघ की मांगों का शासनादेश कराने के लिये बनाया जाएगा सभी पर दबाव

वहीं धरना स्थल पर निर्णय लिया गया कि हड़ताल के साथ मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों का घिराव कर उनके समक्ष भी मांगे रखने के साथ ही उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वह अपने लैटर पेड पर सरकार व शासन को जायज मांगों का शासनादेश जारी करने की संस्तुति करें।

धरने की अध्यक्षता उत्तरकाशी के गणेशमणि बडोनी व संचालक महेन्द्र प्रताप ने किया। धरने पर अशोक ठाकुर, द्वारिका प्रसाद बिजल्वाण, मस्तराम डोभाल, उदयवीर सिंह रावत, चतर सिंह तोमर, नरेन्द्र शर्मा, मुकेश पुण्डीर, कमल डंगवाल, गिरजा शंकर चतुर्वेदी, परमवीर पंवार, विरेन्द्र सजवाण, सुरेश सेमवाल, प्रेम लाल कोठारी व दीपक उपाध्याय आदि मौजूद थे।

धरना देते अमीन संग्रह कर्मी।

आउटसोर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन

देहरादून (एसएनबी)। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति कर्मचारियों का शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अचानक उनकी सेवाओं को संबंधित एजेंसी ने समाप्त कर दिया है। इसलिए समय रहते सरकारी एजेंसी के माध्यम से उनका सेवा विस्तार किया जाए। उधर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि उक्त प्रदर्शनकारियों से उनका कोई वास्ता नहीं है। उक्त ऐजेंसी को आगे कोई काम नहीं दिया जायेगा।

- शिक्षा विभाग ने कहा, कर्मचारियों के साथ कोई समझौता नहीं

बृहस्पतिवार को नन्नूर खेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय के समक्ष धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने मांग न माने जाने तक उनका प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 31 मार्च को उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी है। संघ के अध्यक्ष सुभाष लखेड़ा ने कहा कि सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनका समायोजन किया जायेगा या नहीं। लखेड़ा ने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है।

राजकीय शिक्षक संघ ने की अपर निदेशक से मुलाकात

मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक एनके बहुगुणा से मुलाकात की। पूर्व अध्यक्ष भीम सिंह ने कहा कि एलटी ग्रेड 26 पदों को समाप्त करना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय को बताना चाहिए कि आखिर सरप्लस शिक्षक कहां तैनात हैं। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रही है। उन्होंने इस संबंध में अपर निदेशक माध्यमिक से मांग करते हुए कहा कि वह जल्द उक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करे। जिससे युवा बेरोजगारों में भ्रम की स्थिति टूट सके।

पालीटेक्निक संविदा शिक्षकों का अनशन जारी

देहरादून (एसएनबी)। उत्तराखंड पॉलीटेक्निक संविदा शिक्षकों का धरना 15वें दिन व आमरण अनशन 9वें दिन भी जारी रहा। आमरण अनशन पर बैठे संविदा शिक्षकों की हालत नाजुक होने के कारण पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन संविदा शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। जिससे वह आक्रोशित हैं।

- नौ दिनों से आमरण अनशन पर हैं संविदा कर्मी

बृहस्पतिवार को परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल पर संविदा शिक्षकों की एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वह पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर संविदा शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। सेवा विस्तार सहित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे व आमरण अनशन कर रहे शिक्षकों के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई है। जिसे देखते हुए पुलिस ने कुछ अनशकारियों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने व पुनः आमरण अनशन पहुंच गए। उसके बाद अन्य प्रदर्शनकारियों में आक्रोश और तेज हो गया है। उधर एसोसिएशन के अध्यक्ष सर्वेश चौधरी का कहना है कि बुधवार को भी चार अनशनकारियों को मेडिकल चेकअप के बाद जबरन पुलिस द्वारा अस्स्पताल में भर्ती कराया गया। अभी आमरण अनशन पर चार लोग बैठे हैं।

धरने पर बैठे पॉलीटेक्निक संविदाकर्मी।

स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत स्तर तक होगा पौधरोपण कार्यक्रम

देहरादून (एसएनबी)। स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के लिये सभी कार्यक्रमों का निर्धारण कर लिया गया है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर शासन ने जनपद में तहसील, ब्लाक व पंचायत स्तर पर पौधरोपण कराने के भी निर्देश दिये गए हैं। जिसके लिये प्रशासन ने नोडल अधिकारियों को तैनात कर जिम्मेदारी सौंपी है। कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस के लिये सम्पूर्ण व्यवस्थाओं एवं तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन झरना कमठान ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के लिये जिलाधिकारी ने जिन अधिकारियों को जो जिम्मेदारी एवं दायित्व सौंपे है उन्हें समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के दिये निर्देश

उन्होंने अवगत कराया कि स्वतंत्रता दिवस पर समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा सुबह छह बजे से आठ बजे तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। मुख्य प्रभात फेरी का गांधी पार्क में समापन होगा। उन्होंने कहा शासन के निर्देशानुसार जनपद/तहसील/ब्लाक/पंचायत स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा।

इसके लिये नामित नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम को सम्पन्न कराएंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम का नेहरू युवा केन्द्र में आयोजन किया जाएगा। जिसमें स्वतंत्रता संग्राम व राष्ट्रीय प्रतीकों की बाबत तथा सामाजिक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों आदि पर चर्चा की जाएगी। वहीं जनपद स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता, क्रास कंट्री दौड़ व साईकिल रेस आदि जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराई जाएगी। इसमें रेट के रूट चार्ट का निर्धारण सिटी मजिस्ट्रेट गिरीश चंद गुणवंत द्वारा तय किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा योजना : डाटा एंट्री होने पर मिल रहे फर्जी कार्ड

देहरादून (एसएनबी)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बने राशन कार्डों की डाटा एंट्री होने के साथ ही फर्जी राशन कार्ड सामने आने लगे हैं। इतना ही नहीं गलत तरीके से बने कई राशन कार्डों में जरूरी कागजात तक नहीं हैं। जिसके चलते योजना के वास्तविक पात्र परिवारों के कार्ड नहीं बने और शहर में योजना का लक्ष्य तक पूरा हो गया।

- एक वोटर आईडी का कार्ड के लिए अलग-अलग जगह इस्तेमाल
- बनाये गये कई राशन कार्डों में आवेदन के समय नहीं लगे कागजात

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शहरी क्षेत्र में लोगों को लाभ मिलने लगा है। शहरी क्षेत्र में करीब 53 हजार पात्र परिवार योजना के लिये चयनित किये गये हैं। इसमें अधिकांश लोगों को राशन कार्ड का वितरण कर दिया गया है और उन्हें दुकानों से सस्ता राशन भी मिलने लगा है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कई दुकानों में योजना का राशन तक बंटना शुरू नहीं हुआ है। इतना ही नहीं पात्र परिवारों को शतप्रतिशत कार्ड तक नहीं मिल पाये हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को शतप्रतिशत लाभ देने के लिये बनाये गये राशन कार्डों की डाटा एंट्री कराई जा रही है। इस काम के लिये किसी प्राइवेट संस्था को लगाया गया है।

ऐसे में डाटा एंट्री होने के साथ ही बनाये गये राशन कार्डों में कई फर्जी कार्ड पाये जा रहे हैं। हाल यह है कि अलग-अलग कार्ड में एक ही वोटर आईडी तक का इस्तेमाल हो रखा है, तो कई कार्ड ऐसे बना दिये गये हैं, जिन्होंने पूरे कागजात तक आवेदन के समय नहीं लगाये। जिस कारण शहर का टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन योजना के वास्तविक पात्र परिवार अभी भी कार्ड के लिये चक्कर काट रहे हैं। उधर, इस संबंध में संपर्क करने पर जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य ने बात नहीं हुई।

Himalayan Institute of Technology
Nehru Colony, Haridwar Road, Dehradun

Requirement of faculties in Department of Hotel Management in following field

* Front Office * Food Production
* F&B Service * House Keeping

Candidate should be HM Degree/ 3 years Diploma holder from a reputed institute. Flair for teaching and good communication skills are must.
Send application by post to the institute office with in a week from the date of advertisement along with resume with a latest photograph and photocopies of all relevant certificates or mail to hidehrn@gmail.com, Ph- 0135 2672929. Only shortlisted candidates will be called for an interview.

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

सिद्धहस्तशिल्पियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार-2013 तथा शिल्प गुरू पुरस्कार-2013

राष्ट्रीय पुरस्कार–2013 एवं शिल्प गुरू पुरस्कार–2013 के विचारार्थ/चयन के लिए समस्त भारत के शिल्पियों से विधिवत रूप से भरे गए सहित उत्कृष्ट कलाकृतियों के आवेदन/प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।

पात्रता

राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत में रहने वाले सभी शिल्पकार जो 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जिनके पास 31.12.2012 तक हस्तशिल्प के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो।

शिल्प गुरू पुरस्कार

• असाधारण कौशल वाले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता अथवा सिद्धहस्तशिल्पी।
• 31.3.2012 को हस्तशिल्प के क्षेत्र में 20 वर्ष के अनुभव के साथ आयु 55 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
• शिल्प एवं शिल्प समुदाय के विकास एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

संयुक्त प्रविष्टि स्वीकृत नहीं की जाएगी (केवल असाधारणतम मामले को छोड़कर)

जिन शिल्पीगणों ने वर्ष 2012 के लिए पुरस्कार हेतु आवेदन किया था वे भी वर्ष 2013 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

निम्न केन्द्रों में कार्यालयों से आवेदन प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं और इन्हीं कार्यालयों को विधिवत रूप से भरे गए आवेदन प्रपत्र सहित उत्कृष्ट कलाकृतियों की प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं।

1. क्षेत्रीय निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के पते निम्न प्रकार से हैं—
(i) पश्चिमी खण्ड 8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 (फैक्स : 011-26168479)
(ii) एम एस ओ बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, डी एफ ब्लॉक, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700064 (फैक्स : 033-23345601)
(iii) 26, हैडोज रोड, शास्त्री भवन, चेन्नई-600006 (फैक्स : 044 2827/0/8)
(iv) केन्द्रीय भवन, 7वीं मंजिल, अलीगंज, लखनऊ-226024 (फैक्स : 0522 2329366)
(v) डायरक्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सैन्ट्रल ब्लॉक, तीसरी मंजिल, बेलटाला, गाशिंद रोड दिसपुर, गुवाहाटी-781006 (फैक्स 0361-2230174)
(vi) हारुन हाऊस, तीसरी मंजिल 284, पी मरीअन स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400001 (फैक्स : 022 22660911)
2. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कानपुर।
3. केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम।
4. राज्य उद्योग निदेशालय।
5. जिला उद्योग केन्द्र।

प्रविष्टियां/आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2014 है।

नोट : संशोधन/संवर्धन प्रपत्र, संबंधित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के फील्ड कार्यालयों के पतों को शामिल करते हुए विस्तृत परिपत्र वेबसाइट www.handicrafts.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

जारीकर्ता :
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार
पश्चिमी खंड 7, आर के पुरम, नई दिल्ली – 110066
दूरभाष : 011-26106002, 26191596, फैक्स : 011-26163085

आयुर्वेदिक चिकित्सक भी पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं

हरीश कंडारी

देहरादून। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी एलोपैथी तो दूर आयुर्वेदिक चिकित्सक भी पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं है। सरकार ने लोक सेवा आयोग से चयनित होने पर लगभग 450 आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कहने को पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती दी है लेकिन इसमें लगभग सौ चिकित्सक ऐसे हैं जो सुगम क्षेत्रों में अटैचमेंट का लाभ उठा रहे हैं जिन अस्पतालों में इनकी तैनाती है वह आज भी फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहे हैं।

- सौ से ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सक सुगम स्थानों में
- अटैचमेंट के नाम पर ले रहे हैं सुगम क्षेत्रों का लाभ
- अकेले हरिद्वार जनपद में ही 35 चिकित्सक हैं अटैच

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। लाख प्रयास के बाद एलोपैथी तो दूर सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी पहाड़ चढ़ने में सफल नहीं हो सकी है। किसी तरह अगर सरकार चिकित्सकों को पहाड़ भेज भी रही है तो अटैचमेंट के रूप में चिकित्सकों ने इसका तोड़ निकाला लिया है। हाल ही में लोक सेवा आयोग से 450 आयुर्वेदिक चिकित्सक चयनित हुए थे। सरकार ने इन चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती दी जिससे कि कुछ हद तक पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को राहत मिल सके लेकिन इन 450 चिकित्सकों में से लगभग सौ चिकित्सक ऐसे हैं जो किसी न किसी बहाने से सुगम क्षेत्रों में अटैचमेंट का लाभ उठा रहे हैं। टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं नैनीताल ऐसे जिले हैं जहां से बड़े पैमाने पर चिकित्सक हरिद्वार, हल्द्वानी के सुगम क्षेत्र व ऊधमसिंह नगर के चिकित्सालयों में अटैच हैं। सूत्रों के मुताबित केवल हरिद्वार जिले में ही तकरीबन 35 आयुर्वेदिक चिकित्सक, पिथौरागढ़, टिहरी, एवं पौड़ी जनपदों में ऋषिकुल, एवं गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेजों में रीडर, प्रोफेसर, प्रवक्ता के पद पर तो कोई दाम्पत्य जीवन का हवाला देकर अटैचमेंट का लाभ ले रहा है। देहरादून, हरिद्वार व नैनीताल जिले में जिस अस्पताल में केवल एक पद स्वीकृत है वहां तीन-तीन चिकित्सक अटैच हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का दम भरने वाली सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है।

उत्तराखंड आयुर्वेदिक डाक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. हरीश कांडपाल ने कहा कि सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण यह सब हो रहा है। जहां चिकित्सकों का अटैचमेंट किया है वहां सरकार को नई नियुक्ति करनी चाहिए। जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के लाभ से वंचित न होना पड़े।

श्री श्री 108 महन्त माया गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा 2014

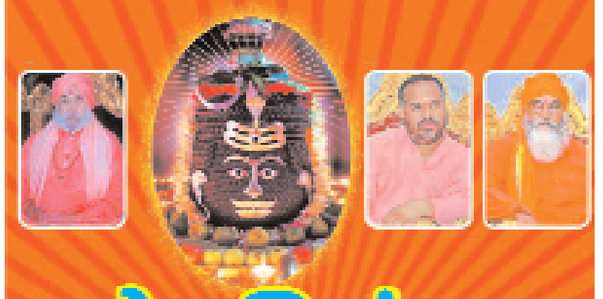

स्नेह निमंत्रण

द्रोणनगरी के सभी धर्मप्रेमी बन्धुओं से निवेदन है कि आदि-अनादि भगवान श्री टपकेश्वर महादेव जी की भव्य शोभायात्रा में सम्मिलित होकर धर्म लाभ कमाएं व विशाल भण्डारे में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करें।

भव्य शोभायात्रा
9 अगस्त, 2014, प्रातः 10.00 बजे
शिवाजी धर्मशाला से
विशाल भण्डारा
दोपहर 1.00 बजे से श्री टपकेश्वर मन्दिर प्रांगण में

आयोजक
श्री टपकेश्वर महादेव सेवादल (पंजी.)
देहरादून